भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3448** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/ 17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर

†3448. श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'क्रूज़ इंडिया मिशन' के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) को एकीकृत करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो एनएमएचसी और समुद्री पर्यटन सर्किटों के बीच प्रस्तावित समन्वय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य के लोथल में एनएमएचसी परियोजना को पूरा करने और चालू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय और क्षेत्रीय तटीय अर्थव्यवस्था पर एनएमएचसी के आर्थिक और रोजगार संबंधी प्रभाव का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रस्तावित रूपरेखा / योजना क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): जी नहीं।

(ग): गुजरात राज्य के लोथल में एनएमएचसी परियोजना के चरण 1ए के लिए पूरा करने की समय- सीमा सितंबर, 2025 है।

(घ): एनएमएचसी परियोजना के विकास से लगभग 22,000 रोजगार का सृजन अनुमानित है, जिसमें 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 7,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। एनएमएचसी के विकास से पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियों, कारीगरों और स्मृति चिन्ह की दुकानों को बढ़ावा मिलेगा। लोथल के आस- पास बेहतर सड़क संपर्कता, सार्वजनिक परिवहन और सुविधाओं से क्षेत्रीय तटीय समुदाय के सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक बढ़ोतरी होगी। एनएमएचसी में समुद्री अनुसंधान संस्थान होगा, जिससे विद्वानों, शोधकर्ताओं और छात्रों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय युवा आतिथ्य, विरासत

प्रबंधन, संग्रहालय संरक्षण और पर्यटन में कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभांवित होंगे। इसके अतिरिक्त, गुजरात राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास और रोजगार तथा क्षेत्रीय तटीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एनएमएचसी साइट के आस-पास लगभग 196 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के समग्र विकास हेतु लोथल क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एलएडीए) का गठन किया है। एलएडीए पर्यटन, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए जोनिंग को बढ़ावा देगा जिससे निजी निवेश आकर्षित होंगे। बेहतर अवसंरचना से व्यापार लागत कम होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और सभी क्षेत्रों से निवेश आकर्षित होगा।

*****